

रेपो रेट में कटौती: महत्त्व व प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

वदिति हो कि आरबीआई ने करीब 10 माह के बाद रेपो रेट में चौथाई फीसद की कटौती की घोषणा की है। दरअसल, औद्योगिक उत्पादन की खस्ताहाल स्थिति के मद्देनजर उद्योग जगत व वशिषज्जों ने नीतगित ब्याज दर में आधा फीसद कमी की उम्मीद लगाई थी। आरबीआई का कहना है कि भूँगाई दर अभी काबू में है, लेकनि अगले डेढ़ से दो वर्षों में यह बढ़ सकती है। हालाँकि, अगली तमिाही में रेपो रेट में फरि से कटौती की जा सकती है।

परमुख बदि

- मौद्रकि नीतकी समीक्षा के लयि गठति छह-सदस्यीय समति(एमपीसी) की सफिरशि पर आरबीआई गवरनर उरजति पटेल ने रेपो रेट में 0.25 फीसद की कमी करते हुए छह फीसद करने की घोषणा की।
- वदिति हो कि वर्ष 2010 के बाद यानी करीब सात साल में यह सबसे कम रेपो रेट दर है। इतना ही नहीं, भारत पहला ऐसा एशियाई देश है, जहाँ इस साल ब्याज दर में कटौती का एलान कयिा गया है।
- इस कटौती के साथ ही साथ रविर्स रेपो रेट दर घटकर 5.75 फीसद पर आ गई है। रज़िर्व बैंक दूसरे वाणज्यिक बैंकों एवं वत्तितीय संस्थानों को अल्पकाल के लयि जसि दर से पैसा उधार देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं, जबकि रविर्स रेपो रेट वह दर है, जसि पर दूसरे बैंक अल्पकाल के लयि रज़िर्व बैंक को पैसा उधार देते हैं।

क्यों बरतनी चाहयि थी सावधानी ?

- हाल ही जीएसटी लागू होने के बाद सेवा क्षेत्र के लयि 18 परतशित का स्लैब तय कयिा गया है, जो कि पहले 15 परतशित था।
- 7वें वेतन आयोग के भतते लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता की करय शक्ति में वृद्धि देखने को मलिंगी।
- वदिति हो कि मुद्रास्फीतकी दर में जो यह गरिवट देखने को मलि रही है, वह खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी के कारण है और इस बात कि कोई गारंटी नहीं है कि मूल्यों में यह गरिवट बनी ही रहेगी।

रेपो रेट और मुद्रास्फीत में संबंध

- जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकों को अपने काम-काज के लयि अक्सर बड़ी रकम की जरूरत होती है।
- बैंक इसके लयि आरबीआई से अल्पकाल के लयि करज मांगते हैं और इस करज पर रज़िर्व बैंक को उन्हें जसि दर से ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं।
- रेपो रेट कम होने से बैंकों के लयि रज़िर्व बैंक से करज लेना सस्ता हो जाता है और तभी बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम करज के तौर पर दी जा सके।
- मुद्रास्फीत बढ़ने का एक मतलब यह भी है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण, बढ़ी हुई करय शक्ति के बावजूद लोग पहले की तुलना में वर्तमान में कम वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं।
- ऐसी स्थिति में आरबीआई का कार्य यह है कि वह बढ़ती हुई मुद्रास्फीत पर नियंत्रण रखने के लयि बाज़ार से पैसे को अपनी तरफ खींच ले।
- अतः आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देता है, ताकि बैंकों के लयि करज लेना महंगा हो जाए और वे अपनी बैंक दरों को बढ़ा दें, जसिसे कि लोग करज न ले सकें।
- पछिले कुछ समय से मुद्रास्फीत में लगातार गरिवट देखी जा रही है, ऐसे में आरबीआई से यह अपेक्षति था कि वह रेपो रेट में कटौती करे।

क्या होगा प्रभाव ?

- आरबीआई के इस नरिणय का प्रभाव यह होगा कि अब बैंकों के पास आसान शर्तों पर करज देने के लयि अधिक पैसा होगा। गौरतलब है कि करज दरें सस्ती होने से अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह से लाभान्वति होती है:

- मकान, कार या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लयि कम ब्याज दर पर करज उपलब्ध होता है।
- जब ब्याज की दर कम होती है तो लोग खरीदारी के लयि उत्साहित होते हैं।
- जब लोग खरीदारी के लयि उत्साहित होते हैं तो बाज़ार में मांग बढ़ती है।
- जब बाज़ार में माँग बढ़ती है तो अधिक उत्पादन की स्थितियिँ बनती हैं।
- जब अधिक उत्पादन की परस्थितियिँ बनती हैं, तब नविशक नए नविश के लयि प्रेरति होते हैं।

- जब नविश बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं।
- जब आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reduction-in-repo-rate-importance-and-impact>

